



2026:AHC:177366

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5189 वर्ष 2026

इंद्र नारायण

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: जादु नंदन यादव, प्रणवेश

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणवेश और राज्य के विद्वान विधि अधिकारी श्री शिव बाबू की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 657 वर्ष 2025 में, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2), 238 भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत, थाना - कोतवाली करवी, जिला चित्रकूट में अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक लगभग 81 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति है; उस पर कोषागार अधिकारियों के साथ मिलीभगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करके अपराध करने और अपने खाते में 28,12,896 रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने का आरोप है। 97 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गबन की गई राशि की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। आगे यह तर्क दिया गया कि सह-आरोपी नरेश दत्त मिश्रा, जिस पर 68 लाख रुपये के गबन का आरोप है, को 11.12.2025 को आपराधिक विविध में पारित आदेश के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है। यह आदेश धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 10416 वर्ष 2025 में पारित हुआ था। सह-आरोपी नरेशदत्त मिश्रा की उपरोक्त अग्रिम जमानत याचिका अभी लंबित है। निवेदन है कि आवेदक की वृद्धावस्था को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि सह-आरोपी माया, जो लगभग 70 वर्ष की महिला हैं, ने गबन की गई 48,49,584 रुपये की राशि वापस नहीं की है और इस न्यायालय ने दिनांक 30.07.2026 के आदेश द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आवेदक द्वारा सार्वजनिक धन का गबन किया गया है और वह इसे वापस करने का इरादा नहीं रखता है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. आवेदक द्वारा गबन की गई कोई भी राशि आज तक वापस नहीं की गई है। सह-आरोपी माया की अग्रिम जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी; उसने भी गबन की गई राशि वापस नहीं की। आवेदक का प्रकरण सह-आरोपी माया के प्रकरण के समान प्रतीत होता है, जो एक महिला थी।



7. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (2024) 12 एससीसी 382

के प्रकरण में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गंभीर प्रकरण में अभियुक्त को अंतरिम सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है। जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होता है। **श्रीकांत उपाध्याय (पूर्व)** के प्रासंगिक प्रस्तर 30 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

“30. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि कई प्रकरण में यह माना गया है कि जमानत एक नियम है, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत एक नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे देने का प्रश्न न्यायालय के सतर्क और विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय, संबंधित न्यायालय को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि गंभीर प्रकरण में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है और विवेचना में काफी बाधा आ सकती है, क्योंकि इससे कभी-कभी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें विचलित करने की संभावना रहती है। हमारा यह मत नहीं है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित गिरफ्तारी से बचाने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश अत्यंत उपयुक्त प्रकरण में ही पारित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होता है। निश्चित रूप से, इससे न्याय के हित में अत्यंत असाधारण प्रकरण में अग्रिम जमानत देने के न्यायालय के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी, लगातार आदेशों की अवहेलना करने और फरार रहने वाले व्यक्ति ऐसी जमानत के हकदार नहीं हैं।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरण में ही दिया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (पूर्व) के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 69 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“69. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी गई शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरण में ही दिया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक विवेक का प्रयोग उचित रूप से आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त प्रकरण है या नहीं। अग्रिम जमानत देना कुछ हद तक अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, इसलिए न्यायालय को अग्रिम जमानत देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में नहीं दी जानी चाहिए और इसे तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायालय आश्वस्त हो कि इस असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।”

9. यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल और एक अन्य , 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528 नामक निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसके प्रासंगिक प्रस्तर 14 और 15 इस प्रकार हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"14.....

74. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें आरोपी द्वारा दी गई जानकारी से महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रासंगिक सूचनाओं का पता चल सकता है। अग्रिम जमानत देने से विवेचना में बाधा आ सकती है। गिरफ्तारी से पहले जमानत का उद्देश्य व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता के अधिकार और विवेचना एजेंसी के अब तक एकत्रित सामग्री के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने और प्रासंगिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए अधिक जानकारी एकत्रित करने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना है।

6.....

75. यह देखते हुए कि गिरफ्तारी कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली विवेचना का एक हिस्सा है, एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एससीसी 303: 2005 एससीसी (आपराधिक) 933 में यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. सामान्यतः, गिरफ्तारी कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आरोपी से अपराध के मकसद, तैयारी, कृत्य और परिणाम के विभिन्न पहलुओं और अपराध में अन्य व्यक्तियों के संबंध (यदि कोई हो) के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चल सके। विवेचना को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने और गवाहों तथा अपराध के पीड़ित से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा करने, उसके लापता होने से रोकने और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा



बन सकती है। विवेचना के दौरान प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता पर संहिता की धारा 438 के तहत दिए गए आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता। विवेचनाकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है और विवेचना प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी अपराध की विवेचना या संज्ञेय अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि संहिता की धारा 438 के तहत दिए गए आवेदन पर विचार करते समय गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो यह विवेचना में हस्तक्षेप माना जाएगा, जो किसी भी सूरत में संहिता की धारा 438 के तहत नहीं किया जा सकता।”

76. सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 514 प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत से संबंधित प्रकरण पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों और मापदंडों को निर्धारित किया। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझना आवश्यक है और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

77. सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 514] और अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए और यह देखते हुए कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एससीसी 379: (2012) 2 एससीसी (आपराधिक) 468] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है और इसके अलावा ऐसी राहत देते समय, न्यायालय को इसके कारणों को दर्ज करना होगा। अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार का हो कि आवेदक को झूठे तरीके से अपराध में फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।" (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरन [डी.के. गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरन, (2007) 4 एससीसी 434 : (2007) 2 एससीसी (आपराधिक) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (आपराधिक) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (आपराधिक) 111])"

आर्थिक अपराध

78. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी गई शक्ति एक असाधारण उपाय होने के कारण, इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए; विशेष रूप से आर्थिक अपराधों के प्रकरण में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे समाज की आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (आपराधिक) 510] प्रकरण में यह माना गया था कि आर्थिक अपराधों में आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।"

15. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह माना कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने की संभावना, साक्ष्य



से छेड़छाड़ या न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने कहा:-

“92.4. अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है; इसी प्रकार, यदि कोई विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं) तो वे किस प्रकार की हैं, यह भी प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है और न्यायालय के विवेक के अधीन है।”

10. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना अभी प्रारंभिक चरण में है और सच्चाई का पता लगाने के लिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। आवेदक के अधिवक्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण झूठा है। इस स्तर पर, अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अभिलेख में आए सबूत और प्रारंभिक विवेचना से आरोपों के लिए उचित आधार स्थापित होता प्रतीत होता है।

11. इस न्यायालय के मतानुसार, नियमित जमानत और अग्रिम जमानत देने के मापदंड अलग-अलग हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जिन आधारों पर किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जा सकता है, वे ही आधार अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबख्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565** के प्रकरण में यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इस न्यायालय की असाधारण शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है।

12. अतः, ऊपर बताए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

13. तदनुसार, यह अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त माना जाएगा।

15. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजें, जो इस आदेश की एक प्रति संबंधित विवेचना अधिकारी को इस आदेश के आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित करेगा।

16. विवेचना अधिकारी विधि अनुसार आवेदक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

21 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे